



सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

मई दिवस को लाल सलाम

मई दिवस शताब्दी पर सीटू जनरल काउंसिल का आह्वान

● मई दिवस की क्रांतिकारी परम्पराओं को आगे बढ़ाओ

● सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा ऊंचा उठाओ, युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में संघर्ष करो

मई दिवस शताब्दी समारोहों पर कलकत्ता में 31 मार्च से अप्रैल 2, 1986 तक सम्पन्न सीटू जनरल काउंसिल की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:

31 मार्च से 2 अप्रैल तक कलकत्ता में हो रही सीटू जनरल काउंसिल की यह बैठक, सारी सीटू राज्य कमेटियों तथा संबद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि इस पहली मई को मई दिवस की शताब्दी समुचित ढंग से मनायें। यह बैठक, इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी तथा दूसरी अनेक राज्य कमेटियों ने इस शताब्दी के पालन के विस्तृत कार्यक्रम तैयार भी कर लिये हैं। जैसा सीटू सेक्रेटेरियट का फैसला था, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कम से कम सात दिन के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए, जो मई दिवस के पालन में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचें।

यह बैठक, देश भर में एकजुट ढंग से शताब्दी समारोह आयोजित करने के लिए सीटू तथा एटक द्वारा 15 फरवरी को जारी संयुक्त विज्ञापन का अनुमोदन करती है और जैसा कि वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस ने भी अपील की है, यह बैठक, राज्य कमेटियों तथा संबद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि मई दिवस की क्रांतिकारी परम्पराओं के आधार पर अन्य ट्रेड यूनियनों को भी साथ मिलाकर यह दिवस मनायें।

इस दिवस पर सरकार की नयी आर्थिक नीति के खिलाफ और रोजगार, जीवनयापन के साधनों, जनवादी अधिकारों तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की हिफाजत के लिए संघर्ष में मजदूर वर्ग के कामों को उभारकर सामने लाया जाना चाहिए। मजदूर वर्ग को, फुटपुस्त ताकतों के खिलाफ और राष्ट्रीय एकता के हक में, संघर्ष के लिए वचनबद्ध होना चाहिए।

यह बैठक, राज्य कमेटियों तथा संबद्ध यूनियनों का आह्वान

करती है कि इन कार्यक्रमों के दौरान एक दिन, बेरोजगारी-विरोधी दिवस के रूप में भी मनावें और काम के अधिकार की संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किये जाने तथा बेकारी भत्ता दिये जाने की मांग उठावें।

मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के इस दिवस पर, इन सौ सालों में मजदूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा की गयी महान प्रगति, जिसके कारण एक तिहाई दुनिया समाजवादी हो चुकी है, पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्था का खात्मा हो चुका है और एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के गुलाम देश, स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में सामने आये हैं, जो याद किया जाना चाहिए।

इस दिवस पर सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा और ऊंचा उठाया जाना चाहिए और मजदूर वर्ग का आह्वान किया जाना चाहिए कि वह सबसे बड़ी युद्धविरोधी ताकत के रूप में सामने आये, अमरीकी साम्राज्यवाधियों तथा उनके नाटो सहयोगियों की युद्ध की साजिशों को भत्तना करे तथा उन्हें बेनकाब करे और समाजवादी शिविर की हिफाजत के लिए, शांति के लिए, दुनिया को नाभिकीय विभीषिका से बचाने के लिए अनवरत संघर्ष चलाये।

शताब्दी समारोहों को ए.यू.सी.टी.यू. (सोवियत संघ) की अपील का प्रचार करना चाहिए और 2000 ईस्वी तक तमाम नाभिकीय व रसायन हथियारों का खात्मा करने तथा नरसंहार के साधनों से मुक्त होकर तीसरी सहस्राब्दी में प्रवेश करने के का. एम.एस. बोर्बाचोव के नये प्रस्तावों के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त करना चाहिए। मई दिवस शताब्दी के समारोह, इसी लक्ष्य की ओर केंद्रित होने चाहिए।

दुनिया भर के मजदूरों एक हो !

अध्यक्षीय भाषण

बी. टी. रणदिवे

साथियों,

सबसे पहले मैं आप सब की ओर से, स्वीडन के दिवंगत प्रधान मंत्री ओलोफ पाल्मे को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँ जो कि हत्यारों के गोशियों के शिकार हुए। उनके निधन से विश्व ने एक बड़ातुड़ा योद्धा को खो दिया है जिन्होंने विश्व शांति की स्थापना और युद्ध के खिलाफ संघर्ष की शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आप सब की ओर से मैं, नस्लवाद के खिलाफ और अफ्रीकी जनता की मुक्ति दिलाने के लिए संघर्षरत उस निर्भीक योद्धा नेल्सन मंडेला की अपनी शुभ कामनाएं भेजता हूँ। पिछले दो दशक के कारावास भी उनके हौसले को तोड़ न सका और जेल में बन्द पड़े यह नेता ही उन दसियों हजार मुक्तिकामी योद्धाओं के प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं जो नस्लवादी तानाशाह बोया निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनकी आवाज जेल के चार दिवारी पार कर उनके दमनकारियों के कानों में चुनौती के रूप में निरंतर गूंज रही है। जिस शर्मनाक और बेहया तरीके से साम्राज्यवादी शक्तियाँ सासकर रीगन की अमरीकी सरकार नस्लवादी बोया हुकूमत को मदद और संरक्षण दे रही है उसके खिलाफ हम सभी को जबर्दस्त रोष का इजहार करते हुए तीव्र-रूप से भर्त्सना करना चाहिए। मैं आप सबकी ओर से नेल्सन मंडेला की निडर पत्नी को भी अभिनंदन देना चाहूँगा जो अपने जनगण को गुलामी के जंजीर में बांधनेवालों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बलूबी निभाने में लगी है।

बाम मोर्चा सरकार—जनतंत्र की अग्रिम चौकियाँ

अन्य विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपकी ओर से प. बंगाल की बाम मोर्चा सरकार का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे उपाध्यक्ष का. ज्योति बसु के नेतृत्व में प. बंगाल की जनता के जनवादी अधिकारों की सफलतापूर्वक रक्षा करती रही है और बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद मेहनत कर्षों के आर्थिक हितों की रक्षा करती रही है। बाम मोर्चा सरकार कायम होने के बाद पिछले आठ सालों से उस राज्य में जनवादी अधिकारों की सम्पूर्ण रूप से रक्षा किया जा रहा है जबकि इसके विपरीत कांग्रेस (आइ) शासित राज्यों में हड़ताली मजदूरों पर बेहिचक लाठी-मोलियाँ वर्षाई जाती हैं, बेरोक-टोक हरिजन की हत्या जारी है। इसके अलावा, सभी कांग्रेस (आइ) शोषित राज्य, सांप्रदायिकतावाद और फूटपरस्त ताकतों के हमले से ग्रस्त है जिनके आगे उनके प्रशासन घुटने टेक बैठे हुए

है। पर प. बंगाल में बाम मोर्चा सरकार की राज में जनता की बढ़ती एकता ने और इस एकता को बरकरार रखने एवं राष्ट्रीय एकता को शक्तिशाली बनाने की बाम मोर्चा सरकार की नीतियों ने इन अलगाववादी तत्वों की हरकतों को नियंत्रण में रखने में कामयाब हुई है। प. बंगाल तथा त्रिपुरा की बाम मोर्चा सरकारें जनवाद की आग्रिम चौकियों के रूप में जनता की एकता की रक्षा कर रही हैं, देश की एकता की हिफाजत कर रही हैं और मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, हरिजनों आदी तमाम उत्पीड़ित तबकों के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा कर रही हैं, निहित स्वाधों के खिलाफ उनके संघर्ष का साथ दे रही हैं तथा जनता की इच्छा के औजार के रूप में प्रशासन का इस्तेमाल कर रही हैं। इन दोनों राज्यों की सरकारें मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं और अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, किसी भी संप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मजदूर वर्ग तथा उसके संगठन इस नीति की बड़ी कद्र करते हैं और इन सरकारों को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं, जिनके खिलाफ केंद्र सरकार तथा शासक कांग्रेस (आइ) द्वारा लगातार साजिशें रची जाती रहती हैं, ताकि इन सरकारों को अस्थिर किया जा सके।

साथियों, आप की ओर से मैं, हमारे सबसे शक्तिशाली आधार, प. बंगाल के जुझारू मजदूरवर्ग को बधाई देता हूँ, मैं जूट मजदूरों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हाल ही में अपने मांगों के समर्थन में सफल संघर्ष चलाया है और जिनका यूनियन बंगाल चटकल मजदूर यूनियन सीटू से सम्बद्ध सबसे बड़ी यूनियन है। बंगाल के मजदूरवर्ग ने हाल के महीनों में अनेक शानदार संघर्ष चलाया है, जबर्दस्त विरोध कार्रवाइयाँ संगठित किया है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने हितों की रक्षा करने में कामयाब हुए हैं। उनके इन तमाम कार्रवाइयों में उन्हें बाम मोर्चा सरकार का समर्थन हासिल था जिसने उनके आंदोलन के लिए पूरी आजादी की सुनिश्चित किया।

प. बंगाल के मजदूरवर्ग ने केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई मूल्यवृद्धि के खिलाफ शानदार विरोध कार्रवाई की शुरुआत की। उनके 11 फरवरी की हड़ताल से ही देश के अन्य भागों में मूल्यवृद्धि के खिलाफ जबर्दस्त संघर्ष कार्रवाइयों की सूचना हुई।

शांति प्रस्तावों की सराहना करो

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की पिछले दिनों सफलतापूर्वक सम्पन्न 27वीं कांग्रेस, हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय

पैमाने पर एक महत्वपूर्ण घटना है। बेरोजगारी से बुरी तरह ग्रस्त तथा अपने औद्योगिक तकनीकी क्रांति के उपलब्धियों को समाज के हित में इस्तेमाल करने में नाकाम पूँजीवादी दुनिया जब गहराते संकट में डुबती चली जा रही है तब सी पी एस यू कांग्रेस ने समाजवादी प्रणाली की सम्पूर्ण उत्कृष्टता का घोषणा किया जिसके जरिए लोगों के जीवन यापन के स्तर को और भी ऊपर उठाने के लिए आर्थिक विकास को त्वरान्वित करने की नई योजना को कार्यान्वित करने जा रही है। और यह सब अमरीकी साम्राज्यवादी और उसके सहयोगियों द्वारा उत्पन्न युद्ध साजिशों के मुकाबले के लिए सैनिक खर्चों में भारी बड़ोत्तरी करने में मजबूर होने के बावजूद भी किया जाना संभव है। कांग्रेस ने अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति और साथ साथ सोवियत संघ की सुरक्षा को शक्तिशाली बनाने की भी दृढ़ संकल्प का इजहार किया। सामाजवादी समाज के विकास के नियमों पर कड़ाई से चलते हुए इस कांग्रेस ने सोवियत संघ के नियोजन की और ज्यादा सफलता का रास्ता दिखाया है और उत्पादन के सम्बन्धों को, औद्योगिक तकनीकी क्रांति के तेजी से विकसित होने के कारण उत्पादक शक्तियों में हुए भारी विकास के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठाये हैं। इन कदमों का लक्ष्य है, ग्रंथर्व्यवस्था में केंद्रीकृत विश्वानिदेशन की दक्षता को बढ़ाना: पार्टी की आर्थिक रणनीति के मुख्य लक्ष्यों को लागू करने में और राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दर व अनुपात तय करने में तथा संतुलित विकास में केंद्र की भूमिका को मजबूत बनाना। इसके साथ ही, इसका मकसद यह भी था कि निचली आर्थिक इकाइयों की रोजमर्रा की गतिविधियों में केंद्र के हस्तक्षेप की परम्परा को खत्म किया जाय।

मई दिवस की क्रांतिकारी परम्पराओं को आगे बढ़ाओ

साथियों, कुछ ही हफ्तों में विश्व भर में मई दिवस शाताब्दी समारोह मनाया जायगा। इस महान् अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस को हमारे तमाम ट्रेड यूनियनों, हमारे राज्य कमेटियों की समुचित रूप से मनाना चाहिए ताकि शिकागो नरसंहार में अपने प्राणों की आहुती देनेवाले उन महान् शहीदों को, जिन्हें पूँजीवादी वर्ग के क्रोध का निशाना बनना पड़ा क्योंकि इन्होंने मजदूर वर्ग का वैहिबक घोषण पर संकुश लगाने के लिए आठ घन्टे के काम की मांग को उठाया था, सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जा सके। यूनियनों को मई दिवस की उन क्रांतिकारी परम्पराओं को याद रखना चाहिए जिन पर चलते हुए आज एक तिहाई दुनिया समाजवादी व्यवस्था तक पहुँच चुकी है, पुराने उपनिवेशवादी प्रणाली टूट चुकी है और गुलामी के जंजीर को तोड़ते हुए एशिया तथा अफ्रीका में विदेशी शासन से मुक्त नवस्वाधीन देशों का जन्म हुआ।

इस दिन को हमारे ट्रेड यूनियनों को मई दिवस की उन क्रांतिकारी परम्पराओं को याद करना होगा जिनपर चलते हुए एक तिहाई दुनिया में समाजवाद की स्थापना हो चुकी है और

जिसकी अवहेलना विकसित पूँजीवादी देशों के मजदूर वर्ग को पूँजीवादी दासता की जंजीरों में बाँध रखा है। मई दिवस का क्रांतिकारी सार इस बात में है कि ऐसी आर्थिक माँगें उठायी जायें (1) जो अपने परिणाम में क्रांतिकारी हैं। (2) पूँजीवादी व्यवस्था का खात्मा करने तथा मजदूर वर्ग की सत्ता व समाजवाद की स्थापना के दृढ़ निश्चय का इजहार हो और (3) सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद तथा मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता की हिफाजत की जाय। मई दिवस की गतिविधियों को कुछ आर्थिक माँगों को उठाने तक ही सीमित कर देना तथा बादवाले दोनों पहलुओं को भुला देना, इस ऐतिहासिक दिवस को उसके क्रांतिकारी सार से वंचित कर देता है। अगर मजदूर वर्ग समाजवाद तक पहुँचना चाहता है, तो वह अपने सामने मौजूद फौरी राजनीतिक कामों की अनदेखी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही, वह अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य को और अपनी कतारों को विभाजित करने की पूँजीपति वर्ग की साजिशों को विफल करने की अपनी जिम्मेदारी को भी भूल नहीं सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर खतरा उत्पन्न होने का एकमात्र कारण है शासक पूँजीपति वर्ग द्वारा संगठित युद्ध। ऐसे तमाम युद्ध साजिशों का विरोध करना और विश्व पूँजीवादी व्यवस्था के खात्मे के लिए संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की एकजुटता का घोषणा करना ही मई दिवस की परम्परा रही है।

युद्ध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता

आज, मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता तथा एकता की रक्षा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की मुख्य बात यह है कि अमरीकी साम्राज्यवाद, समाजवादी सोवियत संघ के खिलाफ नाभिकीय युद्ध की मुहिम चला रही है। युद्ध की यह जो साजिश है वह समाजवाद के खिलाफ साम्राज्यवाद का युद्ध है, पिछले सौ साल में मजदूर वर्ग ने जो जीतें हासिल की है जो कामयाबियाँ पाई हैं उसे खत्म करने की यह साजिश है। यह युद्ध, नव स्वाधीन देशों पर फिरसे कब्जा करने और दुनिया भर पर प्रभुत्व कायम करने की अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध साजिशों का ही हिस्सा है। समाजवादी शिबिर की सैदांतिक व सैनिक शक्ति उनकी इस साजिश के आड़े आ रही है और इसलिए अमरीकी साम्राज्यवाद सोवियत संघ पर युद्ध थोपने की साजिश में सैनिक बड़त हासिल कर रहा चाहती है। और रीगन की अंतरिक्ष युद्ध का कार्यक्रम इसी मुहिम का हिस्सा है। अमरीका की इन युद्ध योजनाओं के विपरीत सोवियत संघ तथा कामरेड गोबार्चेव ने अनेक पेशकश की है ताकि युद्ध की ओर खिसकने को रोका जा सके और धीरे-धीरे तमाम नाभिकीय अस्त्रों को नष्ट कर दिया जा सके। पर अमरीकी साम्राज्यवादी इन प्रस्तावों को ठुकरा रहे हैं।

इन हालात में मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता का तकाजा है कि युद्ध का लगातार विरोध किया जाय और शांति के लिए गोवाँचोव के प्रस्तावों को पूर्ण समर्थन दिया जाय। मई

विषय पर हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि शांति के संदेश को मजदूरों के बीच ले जायें और युद्ध की अमरीकी साजिशों को बेनकाब करें। युद्ध की साम्राज्यवादी साजिशों से समाजवादी शिविर की हिफाजत ही आज सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद का सार है।

ए यू सी सी टी यू की अपील

साधियों, विश्व भर के ट्रेड यूनियनों एवं मजदूर वर्ग के प्रति सोवियत ट्रेड यूनियनों के संघ ए यू सी सी टी यू की अपील से देखा जा सकता है कि स्थिति बहुत ही गम्भीर है। अपील में, जो हमारे संगठन को भी भेजा गया है, इस सदी के अंत तक समूची दुनिया से नाभिकीय अस्त्रों के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए कामरेड्स एम एस गोर्बाचोव द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों के प्रति समर्थन के लिए भी आह्वान किया गया है। इसमें कहा गया, "सोवियत ट्रेड यूनियनों के 13 करोड़ 70 लाख सदस्यों की ओर से ए यू सी सी टी यू, सभी देशों के मेहनतकश लोगों से सभी ट्रेड यूनियन संगठनों से, नाभिकीय अस्त्रों के सम्पूर्ण ख़ात्मे के लिए सोवियत संघ के व्यापक कार्यक्रम के प्रति सम्पूर्ण समर्थन देने के लिए, अपील करती है।"

इसमें कहा गया है कि "सिर्फ सम्मिलित प्रयास के जरिए ही स्थायी शांति की इमारत का निर्माण किया जा सकता है। और इसे और भी विकसित करना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध के खतरे के खिलाफ मोर्चों को हम कितना एकबद्ध कर पाते हैं। विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन की पहल पर चलाये जा रहे अभियान "शांति और नौकरी के पक्ष में ट्रेड यूनियन व मेहनतकश लोग" के जरिए विश्व शांति की सुरक्षा के लिए संयुक्त कार्रवाई का पर्याप्त मौका मेहनतकश लोगों सामने रखा गया है।"

अपील में आगे कहा गया, "हमारा यह विश्वास है कि जब शांति को सुरक्षित रखने एवं नए युद्ध के खतरे को ढालने के लिए संघर्ष का सवाल आयेगा तो सभी ट्रेड यूनियन अपने तमाम विभेदों को अलग रखेंगे और उनके बीच फूट डालने की प्रयासों को शिकस्त देंगे। इसमें हमें उतना ही एकबद्ध होना है जितना हम साम्राज्यमूल्यवादी मार्गों के सवाल पर, जिसे ट्रेड यूनियनों को खत्म करने के लिए आह्वान किया जाता है, होते हैं। सोवियत संघ की ट्रेड यूनियनों की बिचारधारा भी बिलकुल यही है।"

इसमें और देर नहीं किया जा सकता ! 2000 ई. से पहले पहले मानव विनाश के इन हथियारों से दुनिया को मुक्त कराने के लिए आज ही कार्रवाई करना जरूरी है। राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित 1985 का अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष, हमारे समय के इस कठिनतम सवाल—नाभिकीय विनाश को रोकने के सवाल—को मुलभूतनी की दिशा में नया मोड़ देने का वर्ष हो !"

कामरेडों, अंतर्राष्ट्रीय एकता की इस अपील का, जो ऐसी जनता, ऐसे मजदूरवर्ग की अपील है, जिसने मानवजाति को फासी गुलाबी से बचने के लिए दो करोड़ प्राणों का उत्सर्ग किया था, हम सभी को पूरा-पूरा स्वागत करना चाहिए। यह अपील हमें शांति आंदोलन के सिलसिले में अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए आंदोलित करें और अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा उत्पन्न युद्ध के खतरे के खिलाफ तथा शांति की रखवाली के लिए मजदूरवर्ग तथा जनता को लामबंद करने की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।

एक स्वागत योग्य पहल

साधियों, इस क्रम में युद्ध के प्रश्न, रंगभेद के विरोध के प्रश्न तथा फूटपरस्त ताकतों का मुकाबला करने के प्रश्न पर साम्बा समझ बनाने के लिए अनेक ट्रेड यूनियन द्वारा सामना की जा रही व्यापक और प्रमुख समस्याओं के प्रति बढ़ते जागरूकता का ही स्रोतक है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है और इन समस्याओं के प्रति, इस फोरी कलंबिय के प्रति समूचे मजदूर वर्ग को जागरूक बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना होगा।

यह खुशी की बात है कि इंटक द्वारा बुलाई गई बैठक में शिरकत करनेवाले सभी यूनियनों ने उपयुक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक साम्बा मसौदे पर सहमत हुए। इसकी रणनीति विश्व शांति के महत्वपूर्ण सवाल पर संयुक्त अपील तथा संयुक्त प्रचार अभियान में होनी चाहिए ताकि अपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने के लिए समूचे मजदूर वर्ग को जागरूक बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा सकें।

फूटपरस्त ताकतों की भत्सना करो

साधियों, आप सभी इस बात से बाकिफ है कि फूटपरस्त ताकतों की बढ़ती चुनौती से राजनीतिक परिस्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। शासक कांग्रेस (आइ) मुक दर्शक बनी हुई है तथा इन फूटपरस्त ताकतों की बढ़ती चुनौती का मुकाबला करने में बिकल हो रही है और अक्सर उनसे समझौता करने की नीति अपना रही है। पंजाब में स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक ओर पृथकतावाधियों का हमला उग्र से उग्र होता जा रहा है और दूसरी ओर अकाली नेतृत्व उनका मुकाबला करने से डरता है तथा उनके सामने घुटने टेकता जा रहा है। उधर कांग्रेस (आइ) पार्टी, जिसका पंजाब की जनता पर अब भी खास असर है राष्ट्रीय एकता के पक्ष में हस्तक्षेप करने में पूरी तरह नाकाम रही है।

उधर, असम में नयी सरकार फूटपरस्त तथा पृथकतावादी रास्ते पर चल रही है और उसके अनुयायी शासक पार्टी के राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न तथा उनकी हत्याओं का अभियान चला रहे है। राज्य की मौजूदा सरकार ऐसे कदम उठाने की भी तैयारी कर रही है, जिनसे हजारों भारतीय

नागरिकों को विदेशी करार देकर असम से निकाल बाहर किया जायेगा।

फूटपरस्त ताकतों के इस बढ़ते खतरे की पृष्ठभूमि में केन्द्र तथा राज्यों की कांग्रेस (आइ) पार्टी तथा सरकारें अपने निहित स्वार्थों के लिए इन्हीं तर्कों के साथ समझौते करती हैं और ऐसे कदम उठाती हैं, जो सांप्रदायिक तथा फूटपरस्त ताकतों की मदद करते हैं तथा उन्हें बढ़ावा देते हैं। मौजूदा नाजुक हालात के बीच कश्चित राम जन्मभूमि मंदिर के खोले जाने को मुस्लिम जनता के लिए खुला उकसावा ही कहा जा सकता है और कट्टरपंथी सांप्रदायिक नेता इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही, अपने मुस्लिम वोट सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस (आइ) सरकार ने तत्कालगुदा मुस्लिम औरतों के अपने खोहर से गुजरा हासिल करने के अधिकार के मामले में मुस्लिम कट्टरपंथियों के सबसे दक्षिणानुस हिस्से के साथ समझौता किया है। उसने संसद के सामने जो विधेयक पेश किया है, वह एक शर्मनाक तथा विवादास्पद विधेयक है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को काठमुल्लावादी मेड़ियों को सौंप दिया गया है। इससे पहले और कोई केन्द्र सरकार राजीव सरकार की तरह धार्मिक तत्त्ववाधियों के आगे इस तरह घुटने नहीं टेके थे। अपने को इस हद तक गिराने के समर्थन में प्रधान मंत्री को बुलाई दिया है वह शंकराचार्यों द्वारा अस्पृश्यता के समर्थन में दिए जानेवाले बुलाई के ही समान है।

इसके परिणामस्वरूप फूटपरस्त ताकतों को हर जगह अपना सर उठाने में मदद मिला है और मेहनतकश जनता एवं मजदूरवर्ग इससे जबरदस्त रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इन राष्ट्र-विरोधी ताकतों का मुकाबला करने और उन्हें पदों के पीछे से संरक्षण और उकसावा देने वाले साम्राज्यवादी साजिशों को शिकस्त देने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा मजदूर वर्ग को एक साम्राज्य अस्तित्वार करना होगा। राष्ट्रीय अभियान समिति, सांकेतिक ट्रेड यूनियन एवं तमाम क्षेत्रीय फेडरेशनों का यह तात्कालिक जिम्मेदारी बनता है कि वह साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद की ताकतों को शिकस्त देने के लिए लड़ाई के मैदान में उतरें, मजदूर वर्ग की वर्गीय एकता की ताकत का प्रदर्शन करें और देश की एकता की हिफाजत करें, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इन्क की पहल ट्रेड यूनियन आंदोलन को एकजुट होकर लड़ाई के मैदान में उतरने में मदद करेगा।

अप्टाचार के खिलाफ संघर्ष करो

व्यवस्था के गहरे होते चौराफा संकट, जीवन के हर स्तर को प्रभावित कर रहा है और राज्य के बाढ़ राज्य, बाहर दर बाहर में, कानून ब व्यवस्था का खचड़ा बैठता जा रहा है और प्रशासन को निहित स्वार्थों की हिफाजत के लिए नम्र रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। अप्टाचार की संड़ाघ सारे सामाजिक जीवन पर छा रही है। राज्य के मुख्यमंत्रियों से

लेकर मामूली पुलिस और जेल अधिकारी तक अप्टाचार के इस जाल में फंसे हुए हैं। दिल्ली में छूटे हुए अपराधी पैसे के बल पर जेल प्रशासन का बागडोर सम्भाले हुए है और जेल अधिकारियों के सीधे मदद से जेल से भागने में भी कामयाब हुए। इसमें अचरज ही क्या कि घुसखोरी तथा अप्टाचार के इस माहौल में विदेशी खुफियागिरी फल-फूल रही है और विदेशी जासूसी एजेंसियों ने दूर-दूर तक अपना जाल फैला लिया है। दिल्ली में पिछले दिनों सी आई ए के जाल के झंडाफोड़ को हर देशभक्त को गम्भीरता से लेना चाहिए। यह इसका भी सबूत है कि मौजूदा प्रशासन ने देश की सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल दिया है।

यह परिस्थिति, पिछले कई सातों से चल रही अपने ही अर्थनीति को नीचा करके देखने की प्रक्रिया का ही नतीजा है।

आर्थिक नीतियों का जोरदार बिरोध

साधियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले साल राजीव सरकार अपनी नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की जो आधुनिकीकरण के नाम पर मजदूरों के रोजगार पर हमले कर रही है, आम आदमी की ज़िंदगी और डूबर कर रही है। इसके लगातार बुरे असर का प्रतिकलन पिछले बजट में देखा जा चुका है जिसमें पूंजीपतियों को एक हजार करोड़ रु. से भी अधिक की रियायतें दी गई हैं जबकि आम आदमियों पर 1000 करोड़ रु. से भी अधिक का बोझ लाद दिया गया है। इस साल भी प्रशासनिक आदेश के बल पर ज़रूरियात और रोजगारी की चीजों के दामों में बढोत्तरी कर करीब हजार करोड़ रु. का नया बोझ जनता पर थोप दिया गया है। जनता का खून चूसने की इस कार्रवाई के विरोध में अपने रोष का इजहार करते हुए देश भर में आयोजित प्रदर्शन एवं बंद आदि कार्रवाइयों में लोग भारी तादाद में शरीक हुए। इस नीति के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जानी चाहिए और सीटू यूनियनों को जनता पर डाले जा रहे नये बोझ के खिलाफ जन अश्रंतोष को तामबन्द करना जारी रखना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में आयोजित मूकमूल बंद इसी बात को दिखाता है कि अगर कई संगठनों से आह्वान दिया गया तो जनता कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

नई आर्थिक नीति आम जनता पर हमला करने तथा पूँजिपतियों को रियायतें देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उससे बहुत आगे तक जाती है।

यह नीति पिछले खस से पीछे लौटाने की नीति है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण तथा स्वीकृत जरूरत माना जाता था। अपनी खासियों तथा वर्गीय स्वार्थों के बाबजूद इस राष्ट्रीय नीति का मनसब यह तो था ही कि विदेशी पूँजी तथा पश्चिमी हितों की दासता से भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा की जाय।

नई नीति के सिद्धांत हैं— नियन्त्रण हटाना, निजी क्षेत्र को खुली छूट, सार्वजनिक क्षेत्र को लगातार कमजोर करना तथा उसका महत्व घटाना, राष्ट्रीय नियोजन का महत्व घिराना और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए भारतीय बाजारों के द्वार खोलना. संशेष में, सारे देश को निजी क्षेत्र तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय के अनियन्त्रित शोषण के लिए सोना जा रहा है और सरकार एक-एक कर सारे नियन्त्रण हटाती जा रही है.

बहुराष्ट्रीय निगमों से खतरा

भारतीय बाजार में बहुराष्ट्रीय निगमों के घुसपैठ के लिए दी गयी यह आजादी का मतलब न केवल मजदूर एवं जनता का अनियन्त्रित शोषण का ही मौका देना होगा बल्कि यह हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता के कमजोर होने का भी खतरा पैदा करती है. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सिर्फ आर्थिक बाजार पर कब्जा जमाने भर ही संतोष नहीं करती बल्कि दूसरे देशों की सरकारों को गिराने की साजिशें रचती हैं और उन देशों पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व भी कायम करने की साजिश करती हैं. बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर अवलक लगी नियंत्रण को हटाली जा रही है और हमारे देश की जनता को एक भारी राजनीतिक खतरे के सामने धकेल दिया जा रहा है.

सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करना बंद करो

मजदूरों के व्यापक हिस्से और बहुत सारे ट्रेड यूनियन अब तक यह समझते रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के काम-काज और उसके प्रति सरकार की रवैये से उन्हें कुछ लेना देना नहीं. पर एक नव स्वाधीन देश के मजदूरवर्ग के लिए ऐसी उदासीनतापूर्ण रुख गलत है. भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का ब्रिटेन की सार्वजनिक क्षेत्र से तुलना नहीं की जा सकती. गिशाज के तौर पर वहां सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्र साम्राज्यवादी हथियार हैं और राज्य इजारेदार पूंजी के अधीन हैं.

नवस्वाधीन देशों में रणनीतिक उद्योग पर आधारित एक सुगन्धित सार्वजनिक क्षेत्र, साम्राज्यवादी हमलों तथा उसपर निर्भरता से, अर्थव्यवस्था की रक्षा का हथियार साबित होता है. वेशक बहु देशी पूंजीवाद के हित पूरे करता है पर इसके साथ ही बहु अर्थव्यवस्था में साम्राज्यवाद की घुसपैठ की रोकता भी है. यही वजह है कि भारत में जब रणनीतिक महत्व के उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश हुआ तो आगे बढ़े हुए ट्रेड यूनियनों ने तथा तमाम प्रगतिशील शक्तियों ने आमतौर पर इसका समर्थन ही किया था. बड़े पैमाने पर कुप्रबन्ध के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था की स्वतन्त्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसकी एक वजह यह भी थी कि अनेक मामलों में तो इस क्षेत्र को सोधे-सीधे सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी देशों की मदद हासिल थी. सच्चाई यह है कि अगर समाजवादी देशों की सहायता उपलब्ध नहीं होती तो हम

अपने रणनीतिक महत्व के उद्योगों का निर्माण कर ही नहीं पाते.

सार्वजनिक क्षेत्र के इस पहलु को ट्रेड यूनियनों ने सही तरीके से मजदूरों के सामने नहीं रख पाये. आज इसकी जरूरत इसलिए बढ़ गयी है कि साम्राज्यवादी दबाव के आगे आईएमएफ तथा विश्व बैंक के हाथों सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा घटाये जाने का और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की सरकार की नीति बन रही है, और यह यहीं खत्म नहीं हो जाता. सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व घटाने का एक और उद्देश्य है भारत के तकनीकी विकास में मदद के लिए बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों को आमन्त्रण देना.

साथियों, राजीव गांधी की नई नीति सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा घटाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी परिणति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को विदेशी कम्पनियों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय नियंत्रण में पहुँचा देने में भी हो सकती है. सच तो यह है कि ऐसा लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ विदेशों में रहनेवाले भारतीयों के पूंजी के साथ तकनीकी समझौतों के रूप में हो रहा जो कि वास्तव में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ही नकाबपोश प्रति-निधि है.

साथियों, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों ने उनके प्रति प्रशासन की रवैये का जोरदार विरोध किया. निम्नलिखित मांगों पर उन्होंने 13 मार्च को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया: 1. महंगाई भत्ता भरपाई का एक सा स्तर. 2. बोनस पाने की योग्यता सम्बन्धी हदबंदी को हटाने के लिए बोस कानून में उपयुक्त संशोधन, 3. पेशावर कर्मचारियों के लिए आचार संहिता पर खास तौर पर उनके यूनियन बनाने के तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार एवं निर्णय लेने की भूमिका के संदर्भ में आईएलओ कम्पेंडियम को लागू करना, 4. वर्तमान अवकाश ग्रहण सुविधाओं के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना, 5. सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के कानूनी आस्थिति की व्याख्या, 6. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकार की नीतियों खासकर (1) तकनीकी उत्पादन सुविधा एवं श्रम शक्ति में वर्तमान नियमों के सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग के बारे में (2) उदार आयत के बारे में तथा (3) सहभागी प्रबंधन के सिलसिले में एक श्वेत पत्र जारी करना.

सीढ़ इन मांगों का समर्थन करती है जिसमें से कई न केवल अधिकारियों के हित में है बल्कि सारे देश की हित में भी है.

बहुराष्ट्रीय निगमों का पडयंत्र

देश भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर अधिकारियों के संगठन ने सार्वजनिक क्षेत्र को नीचा दिखाने की सरकार की

वर्तमान नीतियों की और उसे उचित ठहराने की उनके दावे का पर्दा फाँस कर दिया है, वे कहते हैं "सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगितामूलक भावना का अभाव तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के सामने उसे खड़ा कर देने से ऐसे उद्यमों को बुस्त दुरुस्त किया जा सकता है यह कहना सार्वजनिक क्षेत्र पर एक ओर हमला है, यह नीति तो सिर्फ इस मूल सच्चाई को छिपाने का एक प्रयास है और सच्चाई यह है कि कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ मंदी से बुरी तरह प्रभावित हैं और भारतीय बाजार को हासिल करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, वे आगे कहते हैं, क्या यह अचरज की बात नहीं कि जब भारतीय जहाज निर्माण कारखाने आर्डर के लिए तरस रहे हैं तब भारत सरकार एस ए एफ ए यू एन योजना के तहत भारतीय व्यापारी बेड़ा को जहाजों की आयात के लिए इमदादी रकम दे रही है? इसी तरह, जबकि कोई भी देश अगर वह खुद विजली शक्ति संयंत्र बनाती है तो उसकी आयात की इजाजत कभी नहीं देती, पर 'भेल' को भूला रखकर हमारे देश में विश्व व्यापी आयात की खुली आजादी दी गई है, अखबारों में छपे खबर के मुताबिक भारत हेमो इलेक्ट्रोक्लस (भेल) के चेयरमैन ने कहा है, "कोई भी देश अपने स्वदेशजात उद्योग को बर्बाद नहीं करता, हमें इस बात की निश्चिन्ता लगी है कि अगर आर्डर बाहर भेजा जाता है तो भेल की क्षमता का उपयोग काफी हद तक घट जायगा, हमें आर्डरों के लिए लड़ना होगा।" "इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेना होगा कि तकनीकी विकास का कोई सांख्यिकी उपयोग नहीं, एक सीमित बाजार में तकनीकी आयात वास्तव में उस बाजार में घुसने का, और वह भी प्राथमिकता के आधार पर, एक विकल्प है, भारतीय वैज्ञानिक तथा तकनीकविद, औद्योगिक तकनीक की अधिकांश माँग पूरी करने में समर्थ हैं, अगर अभाव है तो आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए अवश्यक राजनीतिक इच्छा का, हम सार्वजनिक क्षेत्र अधिकारियों के प्रतिनिधि, जनता को सूचित करना चाहेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र को नीचा दिखाने तथा संयंत्र व तकनीकी, दोनों के आयतों को उदार बनाने की सरकार की वर्तमान नीतियों का आनेवाले दिनों में विनाशकारी परिणाम निकलना तय है।"

नई आर्थिक नीतियों के बारे में हमारी आशंका अब अधिकारियों के संगठन ने सम्पूर्ण रूप से समर्थन किया है, वे भी अब यह महसूस करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतियोगिता के सामने खड़ा करने के नाम पर बहुराष्ट्रीय निगमों की घुसपैठ होनी और इससे देश के हितों तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए खतरा पैदा हो जायेगा।

प्रबंधन का जनवादीकरण करो

इन परिस्थितियों में, यह बहुत जरूरी है कि मजदूरों, अधिकारियों तथा प्रबंधकों के बराबरी के आधार पर सम्पूर्ण हिस्सेदारी के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जनतांत्रिक प्रबंधन

की व्यवस्था लागू की जाय, सार्वजनिक क्षेत्र को विदेशी प्रति-योगिता के सामने खड़ा करने के बजाय इसमें जनतांत्रिक तथा सहभागी प्रबंधन के लिए द्वार खोले जाने चाहिए ताकि देश के हित में इसकी सक्षमता को बढ़ाया जा सके।

साधियों, सीढ़ हमेशा से यह माँग करती रही है कि गुप्त मतदान के जरिए मजदूर प्रतिनिधियों के चुनाव के अचार पर प्रबंधन में मजदूरों की बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, अगर कारखानों तथा प्रतिष्ठानों को चलाने में सारे मजदूरों को शामिल करना है और उन्हें देश के हित में कार्यकुशलता बढ़ाने में सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित करना है, तो ये दोनों ही शर्तें पूरी करना जरूरी है, लेकिन सरकार इनमें से एक भी शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और मजदूरों के हिस्सेदारी का नाटक ही करना चाहती है, मजदूरों की बराबरी की हिस्सेदारी का दर्जा न तो मानती है और न ही देना चाहती है, ये इस बात को मानने से इन्कार करती है कि मजदूरों के प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्तमतदान के जरिए होना चाहिए, ये ट्रेड यूनियन सदस्यता, और वह भी चेक ऑफ प्रणाली के आधार पर, के लिए मतदान से अधिक और कुछ स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, जाहिर है कि इससे मजदूर वर्ग का एक खासा हिस्सा बाहर रह जायेगा जिन्हें उत्पादन कुशलता बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी।

गुप्त मतदान की माँग का सरकार विरोध करें, यह तो समझ में आता है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि ट्रेड यूनियन संगठनों का एक हिस्सा क्यों इस मामले में सरकार का साथ दे रहा है, यह, मजदूरों के व्यापक हिस्से में आस्था का अभाव तथा किसी प्रतिष्ठान को चलाने में तमाम मजदूरों को शामिल करने की जिम्मेदारी में सामियों को ही दिखाता है।

उद्योगों की महामारी

साधियों, औद्योगिक उत्पादन की दर में बड़ोत्तरी के सरकारी दावे के बावजूद बीमार उद्योगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, इस समय 500 से अधिक बड़े कारखाने और 90 हजार से ज्यादा छोटे कारखाने बीमार हैं, यह स्थिति मजदूरों के लाखों परिवारों पर अकथनीय मुसीबतें डाल रही है जिससे निकट भविष्य में निजात पाने की कोई आसरा नहीं।

दूसरी ओर, हालात इसी बात की ओर निर्देश करता है कि स्थिति और भी कठिन होने जा रही है तथा सरकार की उदार आयात नीति के कारण और भी इकाइयों का बन्द हो जाना या बीमार होना तय है, आयात के विभिन्न रियायतें दिए जाने और इसे उदार बनाने के कारण बहुत सारे उद्योग बन्द हो जाने के कगार पर हैं, सिर्फ मुट्ठी भर कुछ बड़े बड़े उद्योग एवं इजारेदारों ही इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और उनके यहाँ नये आधुनिक मशीनें तथा कंप्यूटर लगाये जाने के कारण रोजगार के अवसर भी संकुचित हो गया है।

इजारेदारों का बोलबाला

नयी नीति से लाभान्वित होने वालों का चेहरा, 22 मार्च को 'इकोनोमिक टाइम्स' में किड्डी के अख्यक्षार, पी. गोयंका द्वारा की गई भारतीय अर्थनीति की समीक्षा से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. गोयंका का कहना है कि, "उद्योग ने नये मौके के अच्छे परिणाम दिये हैं... दिसम्बर 1985 के अन्त तक बिकेन्द्रीकृत 25 बड़े उद्योग समूह में करीब 1196 पंजीकरण हुए हैं, 17 एम आर टी पी तथा 27 नैर-एम आर टी पी कंपनियाँ अपने आधार बड़ा बनाने सम्बन्धी सुविधाओं का फायदा उठाया है. एम आर टी पी कानून की धारा 21 तथा 22 से जिन एम आर टी पी कंपनियों को छूट मिली हुई है वह भी अपना पैसा खासकर इलेक्ट्रानिक उद्योग में लगाया है जिसकी कुल लागत 2,889 करोड़ रु. के करीब है."

आज हमारे सामने यह स्थिति है और इन हालात का तकाजा है कि हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन इस नई नीति का कड़ा प्रतिरोध करें. इसके लिए व्यापक एकता और एकजुट कार्रवाइयों की जरूरत है.

मजदूरों पर अकथनीय मुसीबतें

कपड़ा तथा जूट मजदूरों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं. और भी कपड़ा मिलें बन्द हो रही हैं. हाल में, एन टी सी ने चार अन्य मिलों को भी बन्द कर देने की घोषणा की है जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे. इसलिए हमें कपड़ा तथा जूट उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए. ट्रेड यूनियन आंदोलन, किसी भी राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान में, अपने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तथा उत्पादन कुशलता बढ़ाने की समस्याओं सहित अन्य तमाम समस्याओं पर एवं राष्ट्र की जनता की तथा मजदूरवर्ग के हित में उद्योग के आधुनिकीकरण के सवाल पर भी विचार-विमर्श के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

बढ़ती बेकारी

साथियों, सहरी तथा वेहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने से उत्पन्न भीषण स्थिति से और कोई भी ज्यादा दुखदायी समस्या आज हमारे सामने नहीं. रजिस्टरशुदा बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ पर पहुंच गई है, हालांकि यह संख्या भी बेरोजगारों की वास्तविक संख्या से बहुत कम है क्योंकि इनका एक विशाल हिस्सा अपने नाम तक दर्ज कराने कि बिना ही नहीं करते. ग्रामीण बेरोजगारों की सही संख्या का पता किसी को भी नहीं है. इनकी संख्या चार-पांच करोड़ या उससे भी अधिक हो सकती है. हर साल हजारों नौजवान एवं महिलाएं दिल में उमंग और मन में आशा लिए अपने स्कूल, कालेजों की पढ़ाई समाप्त कर नौकरी के बाजार में आते हैं जहाँ उन्हें निराशा ही मिलती

है. राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें योगदान देने से वंचित रहना पड़ता है. रोजगार न मिलने के कारण उन्हें दूसरे पर आश्रित होकर अपमानभरी जिंदगी बसर करते में मजबूर होना पड़ता है. भारत के करोड़ों युवाओं के सामने भविष्य आज निराशापूर्ण और अंधकारमय हो रहा है. कांग्रेस शासन के चाखीस सालों ने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को सामाजिक हत्या के हालात पैदा कर दिए हैं. हमारे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन, सीटू तथा उसकी यूनियनों, सभी की इसके लिए कड़ी आलोचना की जानी चाहिए कि उन्होंने मजदूर वर्ग की इस युवा पीढ़ी की उपेक्षा की है और अपने आप को स्थायी रोजगार में लगे मजदूरों के बेतन आदि की रक्षा तक ही सीमित रखा है. इस प्रकार तो ट्रेड यूनियन आंदोलन युवा पीढ़ी को पूँजीवादी रास्ते के संकट के लिये बलि का बकरा बनाने की पूँजीपति वर्ग की साजिश में ही हाथ बँटाता है.

साथों ही कोई राज्य कमेटी यह दावा कर सकती है कि बेरोजगारों को लामबन्द करने तथा उन्हें तात्कालिक राहत दिलाने के लिए उनसे कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हों. बेरोजगारों की बढ़ती कतार के आँकड़े दर्शाने के सिवा उनके लिए बहुत कम ही कुछ किया गया है. भूल मार्च, तात्कालिक राहत के लिए सीधे उनके मांगों को लेकर कार्रवाई आदि कार्यक्रम के जरिए ही संगठित मजदूरवर्ग आंदोलन इस महत्वपूर्ण हिस्से को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लामबन्द कर सकते हैं.

प. बंगाल सरकार ने बेरोजगारों को राहत दिलाया है पर कांग्रेस(आई) सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है. कांग्रेस(आई) ने, कम से कम उनके कुछ नेताओं ने समस्या को सुलझाने के लिए भूमिपुत्र के नाम पर मजदूरों के ही एक हिस्से को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें की हैं.

मई दिवस शताब्दी आयोजनों में अलग से एक दिन तय किया जाना चाहिए, जिस दिन बेरोजगारों की मांगें उठायी जायें और काम का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किए जाने की मांग उठायी जाय. मजदूरों को बताया जाना चाहिए कि काम का अधिकार महज एक स्वप्नभर नहीं है बल्कि सभी समाजवादी देशों के संविधानों का अविभाज्य हिस्सा है. इसे हासिल करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक सत्ता मजदूर वर्ग तथा जनता के हाथों में हो.

जनरल काउंसिल को राज्य कमेटियों की निर्देश देना चाहिए कि बेरोजगारों को संगठित करने के कारण कदम उठायें, उनके सम्मेलन बुलायें, उनकी मांगें उठावें और उनकी मांगों के पक्ष में संगठित मजदूरों को लामबन्द करें.

संगठित आंदोलन को कम्प्यूटराइजेशन, खाली स्थान भरने से इनकार, नई भर्ती पर रोक, अनिवार्य या कथित ऐच्छिक रिटायरमेंट जैसे ऐसे सभी सरकारी कदमों व योजनाओं के

(शेष पृष्ठ 26 पर)

संगठन को शक्तिशाली बनाओ

● सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा ऊंचा उठाओ, युद्ध के खिलाफ तथा शांति के पक्ष में संघर्ष करो !

● फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ, प्रतिगामी श्रायिक नीतियों के खिलाफ, क्लोजर व तालाबंदियों के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ और जनवाद के पक्ष में संघर्ष को तीव्र करो !

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट आंदोलन को तेज करने के साथ-साथ संगठन की स्वतन्त्र गतिविधियाँ बढ़ाओ—यह थी कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल 1986 को सम्पन्न सीटू जनरल काउंसिल बैठक का आह्वान. अध्यक्षीय भाषण और फिर महासचिवीय रिपोर्ट में इन जिम्मेदारियों को सीटू राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों को सौंपा गया ताकि वे मेहनतकश जनता के व्यापकतम हिस्से को तामश्वर कर साम्राज्यवादी-जंगलों के खिलाफ शांति के रखवाले एक जबर्दस्त शक्ति के रूप में उभर सकें; साम्राज्यवादी एजेंसियों के शाह पर पनप रही अंदरूनी फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ एक महान शक्ति के रूप में उभरें तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें. साथ-साथ उन्हें सरकार की नयी श्रायिक नीतियों के खिलाफ दृढ़ संघर्ष भी चलाना होगा क्योंकि राजीव सरकार विदेशी पूँजी तथा विश्व बैंक व आईएमएफ के इसारों पर जिस श्रायिक नीति को अपनाया है उससे जनता के सभी तबकों पर भारी असर पड़ रहा है. बढ़ती महंगाई, तालाबन्दियाँ, मिलबन्दियाँ, औद्योगिक रूग्णता और तेज रफ्तार से बढ़ती चली जा रही बेरोजगारी की संख्या, विकास के पूँजीवादी रास्ते पर चलने का नतीजा जो ही सामने लाती है. इसके अलावा, इजारेदारों और भूस्वामियों को नीहित स्वार्थों पर रोक लगाकर उनसे साधनों को लेने के बजाय उन्हें खुली छूट दी जा रही है, सार्वजनिक क्षेत्र को गिराया जा रहा है और निजी क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है और इस तरह मजदूर-वर्ग को पूरी तरह बहुराष्ट्रीय निगमों और उनके सहयोगी भारतीय इजारेदारों के शोषण का निशाना बना दिया है. अध्यक्षीय भाषण, महासचिवीय रिपोर्ट तथा श्रायिक नीति पर अपनाए गए प्रस्ताव के जरिए श्रायिक नीतियों में इस प्रतिगामी बदलाव की ओर जिससे सरकार की गुटनिपेक्ष विदेश नीति पर, तथा देश की आजादी और संभ्रमता पर गहरा असर पड़ सकता है, सबस्यों का ध्यान आकर्षित किया और इसे एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन की सम्पूर्ण ताकत लगाकर बदलने के लिए आह्वान किया गया. इसके साथ ही सीटू यूनियनों को सरकार की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ तथा जनता के जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट ट्रेड यूनियन कार्रवाई के

लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज करने को कहा गया. स्थिति की यह माँग है कि इन बहुमुखी चुनौतियों के मुकाबले के लिए सीटू यूनियनों को अपने गतिविधियों का विस्तार करना होगा. बैठक ने अपने राज्य कमेटियों एवं तमाम यूनियनों का आह्वान किया है कि वे मई दिवस शताब्दी समारोह को, मई दिवस की श्रितिकारी परम्पराओं के आधार पर समुचित ढंग से मनाएं.

जनरल काउंसिल की मीटिंग का, वी.टी.आर. के अध्यक्षीय भाषण से शुरू हुई जिसके बाद का. समर मुखर्जी ने चार्टरों पर, स्वीडन के प्रधानमन्त्री ओलोफ पाल्मे की नृसंह हत्या पर, का. रामदास के निधन पर प्रस्ताव पेश किए.

इसके बाद प्रस्ताव उपसमिति तथा कैंडिडेट्स उपसमिति का चुनाव किया गया. प्रस्ताव उपसमिति में पी.के. गंगुली संयोजक और पी. सांभगिरि, सुनील बसुराय, बीरेन राय तथा एन. पञ्चोत्तन एवं कैंडिडेट्स उपसमिति में पी. सत्यनारायण संयोजक और ए.के. पञ्चानन, काली घोष तथा रंजित बसु सदस्य चुने गए.

का. एम.के. पंधे ने इसके बाद दुर्गापुर में 28 व. 29 मार्च को हुई सार्वजनिक क्षेत्र यूनियनों की समन्वय समिति की बैठक की रिपोर्ट पेश की जिसमें 21 मई को सार्वजनिक क्षेत्र दिवस मनाते का निर्णय लिया गया.

महासचिव की रिपोर्ट में मुख्यतः 1985 की मई से मार्च 86 के बीच की अवधि में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा प्रस्तुत की गयी. सरकार की नीति में आये प्रतिगामी बदलाव की ओर ध्यान खींचते हुए, रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि इन नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है. इस पर भी गौर किया गया कि इस समय अनेक संघर्ष ऐसे संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो किसी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध नहीं हैं. इन संघर्षों के साथ एकजुटता प्रकट करने के मामले में ट्रेड यूनियनों की तत्परता मजदूर वर्ग को, राष्ट्रीय अभियान समिति से भी कहीं ज्यादा व्यापक स्तर पर एकजुट कर सकती है—जैसा कि तमिलनाडु में पिछले नवम्बर-दिसम्बर में शिक्षकों की हड़ताल के समय देखने में आया था.

इसके साथ ही, रिपोर्टों में इस पर भी गौर किया गया कि राष्ट्रीय अभियान समिति का शुर्भाला बेग अब किसी हद तक कम हो गया है। फिरभी, जिनकी की सच्चाइयाँ ऐसी ट्रेड यूनियनों को भी एकजुट होने के लिए मजबूर कर रही हैं, जो पहले साथ आने को तैयार नहीं थीं। 12 सितम्बर 1985 का पश्चिम बंगाल का बन्द इसकी मिसाल है। रिपोर्टों में इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा गया कि सरकार द्वारा स्वीकार की गयी विभिन्न नीतियों के चलते, रोजगार पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू भी हो चुका है। इस संदर्भ में बेरोजगारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा कामगार महिलाओं को संगठित करने के लिए विशेष कदम उठाये जाने के सुझाव के साथ ही रिपोर्टों में इस पर गौर किया गया कि जनता के नये से नए तबकों संघर्ष के मैदान में उतर रहे हैं। इस सिलसिले में सौदू अध्यक्ष के भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों की एसोसिएशन के आपन की चर्चा की ओर पुनः ध्यान खींचते हुए महासचिव ने इस पर जोर दिया कि सौदू को बराबर स्थिति की समीक्षा करते रहना चाहिए, कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए और संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि संगठन अपने सामने मौजूद जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। समर मुखर्जी ने, जातीय श्रमिक जोत के सालाना सम्मेलन के सिलसिले में अपनी वंगला देश यात्रा की भी रिपोर्ट पेश की।

सौदू के 19 में से 15 केंद्रीय पदाधिकारियों, 344 में से 231 जनरल कार्डसिल सदस्यों और आमवित सदस्यों ने जनरल कार्डसिल की इस बैठक में हिस्सा लिया।

विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे 27 जनरल कार्डसिल सदस्यों ने रिपोर्ट पर हुई बहस में हिस्सा लिया। संयुक्त संघर्ष के अपने अनुभव प्रस्तुत करते हुए अनेक प्रतिनिधियों ने बताया कि किस प्रकार राष्ट्रीय अभियान समिति के कुछ घटक राज्य स्तर पर अभियान समिति के कार्यक्रमों के पालन के लिए एकजुट होने से किसी न किसी महाने से बचने की कोशिश करते हैं। बहस के दौरान यह तय पाया गया कि ऐसे घटकों को संयुक्त कार्रवाई के लिए राजी करने के प्रयास जारी रखने की, सौदू को मजबूर बग का सीधे आह्वान करना भी जारी रखना चाहिए और सौदू केन्द्र को समय-समय पर रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। विभिन्न राज्य कमेटियों ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान खींचा कि राज्य स्तर पर ऐसे अनेक संगठन सक्रिय हैं, जो राष्ट्रीय अभियान समिति में शामिल नहीं हैं, मसलन तमिलनाडु में डी एम के से सम्बद्ध मजदूर संगठन, बम्बई के औद्योगिक क्षेत्र में एच एम के की कार्यवाही, लिहाजा, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय अभियान समिति की इकाईयों के रूप में काम करना ही काफी नहीं होगा। इसके अलावा, लाखों की सदस्यतावाली केंद्रीय फेडरेशनों की मौजूदगी भी, जो मुख्य निर्णायकरी निकाय में नहीं है, कठिनाईयों पैदा करती है। इन मसलों पर गौर किया जाय और राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा कन्वेंशन की तैयारी की जा रही है, उसे सफल बनाया जाय।

जनरल कार्डसिल सदस्यों की रिपोर्टों से यह तथ्य भी सामने आया है कि अनेक राज्य कमेटियाँ, शिकागो के मई दिवस नरसंहार की शताब्दी के पालन के कार्यक्रम तय भी कर चुकी हैं।

बहस में हिस्सा लेने वालों में, आर. उमानाथ, एन. पपलोचन, सी. नांजुदाया, पी. साभाशिरि, एन. प्रसाद राव, वीलत राम, चण्डी प्रसाद, कृपंतराम, अमन घोष दस्तदार, एस. कुमार, शिवाजी पट्टनायक, मण्णकान्त, मोहनलाल, सुबोध मेहता, एस.एन. सोलंकी, सीताराम मंजरेकर, के.एन. रवीन्द्र-नाथ, मनोरंजन राय, चिन्मय मजुमदार, दिवीष मजुमदार तथा बी. बेरियन शामिल थे।

रिपोर्टों से यह भी साफ था कि राज्य कमेटियाँ खुद इस समस्या के प्रति सजग हैं कि संगठन की समस्या, सौदू की वास्तविक शक्ति को प्रतिबिम्बित नहीं करती है, यह महसूस किया गया कि सदस्यता रिटर्न भेजने में ढील की समस्या पर जल्द से जल्द कार्रवाई पाया जाना चाहिए। बहस के दौरान इस सिलसिले में कुछ सुझाव भी आये।

इसके बाद सौदू महासचिव समर मुखर्जी ने बहस का जवाब दिया और सौदू को मजबूत करने के आह्वान के साथ, ताकि वह जनता के विभिन्न तबकों के संघर्षों को नेतृत्व प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके, बहस का समापन किया। इसके बाद, स्वीकार करने योग्य सुझाव शामिल किये जाने के निर्णय के साथ रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गयी।

जनरल कार्डसिल ने बहस के बाद अनेक प्रस्ताव स्वीकार किए, जिनमें ए यू सी सी टी यू की अपील, अंगोला तथा अफगानिस्तान में प्रतिक्रान्तकारी विरोधों को अमरीकी मिसाइलों की सलाह, समाचारपत्र कर्मचारियों की हड़ताल के लिए समर्थन, प्रतिगामी आर्थिक नीति, श्रीलंका के जातीय अधिकों की समस्या, फूटपरस्त ताकतों की चुनौती, मुस्लिम महिला विधेयक, पंजाब की स्थिति, असम की स्थिति, कोयला मजदूरों की प्रस्तावित हड़ताल के लिए समर्थन, तालाबन्दी-मिलवन्दी-औद्योगिक बीमारी, जूट-कपड़ा-चीनी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, बेरोजगारी, समान काम के लिए समान वेतन, सरकारी कर्मचारियों का बचाव पेश करने का अधिकार, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, नयी शिक्षा नीति आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव मुख्य हैं।

सौदू के छठे सम्मेलन के आयोजन के प्रश्न पर भी प्रारंभिक विचार-विमर्श हुआ। सम्मेलन के आयोजन के लिए सौदू की केरल राज्य कमेटी से अनुरोध करने की राय बनी। केरल के प्रतिनिधियों ने यह अनुरोध राज्य कमेटी के सामने रखने का वचन दिया। राज्य कमेटी के फैसले के बाद, सौदू सेक्रेटरीयट इस सिलसिले में अंतिम रूप से निर्णय लेगा।

केरेंसियल-सब-कमेटी के संयोजक पी. सत्यनारायण ने बताया कि 114 नयी यूनियनों ने सम्बद्धता के लिए आवेदन किया है, जिनकी कुल सदस्य संख्या 34,738 है। इनमें से 81

यूनियनों को, जिनकी सदस्य संख्या 27,166 है तत्काल संबद्धता से ही गयी, जबकि शेष 33 यूनियनों को, जिनकी कुल सदस्य संख्या 7,572 है तथा जिनके प्रार्थनापत्रों में कुछ त्रुटियाँ थी, इस शर्त के साथ संबद्धता प्रदान कर दी गयी कि वे संवैधानिक शर्तों पूरी करेगी।

बैठक में, मई दिवस के मौके पर एटक के साथ संयुक्त घोषणापत्र जारी करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया और सेक्रेटेरियट को इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। यह सुभाष भी दिया गया कि अगर सम्भव हो, संयुक्त अपील में अन्य ट्रेड यूनियनों को भी एकजुट किया जाय।

जनरल काउंसिल के विचार-विमर्श का समाहार करते हुए सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने कहा कि सीटू कार्यकर्ताओं ने अब राज्यों में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति का विश्लेषण करना तथा उसकी तस्वीर पेश करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश तथा कानपुर की खास तौर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सीटू यूनियनों को, दमन का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। एक समस्या यह जरूर है कि राज्य कमेटियाँ आज भी स्थिति की समग्र तस्वीर पेश नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कार्यालय, इस सिलसिले में राज्य कमेटियों को मदद करेगा। फिर भी, समुचित रिपोर्टें प्रस्तुत करने की और दूसरों के साथ अनुभव बांटने की—जिससे कि एक सही दृष्टिकोण विकसित हो सके—मुख्य जिम्मेदारी राज्य कमेटियों को ही उठानी होगी।

बी.टी.आर. ने आगे कहा कि आज भी सीटू के नेतृत्वकारी कार्यकर्ता, विदेश नीति सम्बन्धी प्रश्नों या बेरोजगारी, फूटपरस्त ताकतों की बढ़ती चुनौती आदि राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर, पर्याप्त तीव्रता से सक्रिय रूप नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार को दोषी ठहराने तक सीमित रहने का परम्परागत ट्रेड यूनियन रवैया बरकरार है। इसीका परिणाम है कि ट्रेड यूनियन, गुटनिष्ठाता की नीति के महत्व को भी नहीं समझ पायी है, जबकि इस नीति का सार साम्राज्यवादविरोधी है। इसी प्रकार, वे बेरोजगारी की समस्या को समुचित ढंग से नहीं उठा रही हैं। पहले ही यह आरोप लगाया जाता रहा है कि ट्रेड यूनियन सिर्फ संगठित क्षेत्र के मजदूरों, महिला कामगारों, बेरोजगारों आदि की समस्याओं पर कोई ध्यान ही नहीं देती हैं। सीटू अध्यक्ष ने आह्वान किया कि मई दिवस के समाह भर के कार्यक्रमों में, एक दिन पूरी तरह से बेरोजगारी की समस्या को समर्पित होना चाहिए और काम के अधिकार की मांग को लेकर, जोरदार आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 घंटे के श्रम दिन की तरह, काम का अधिकार भी एक बुनियादी अधिकार है और इस साल इस बुनियादी मांग को उठाया जाना चाहिए।

संयुक्त मोर्चों के कामकाज के अनुभव का विश्लेषण करते हुए बी.टी.आर. ने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि यह संयुक्त मोर्चा महज एक कार्यनीति है। सीटू, इसे एक बुनियादी रणनीति मानकर काम करती रही है, जिसके जरिए मजदूरों को, सुधारवादी ट्रेड यूनियन लाइन से हटाकर क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन लाइन की ओर लाया जाता है। इस सिलसिले में डेढ़ दशक से ज्यादा के अनुभव का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए बी.टी.आर. ने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ही आज सीटू उस स्थिति में पहुँची है, जहाँ उसकी अनदेखी करके नहीं चल सकते। अपनी इस हैसियत को सीटू, सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूरों को लाभबन्ध करने के लिए इस्तेमाल करती है।

उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर किए जाने पर पहले ही जनता के ऐसे सभी तबकों ने विरोध प्रकट किया है, जो अतन्त्र तथा धर्मनिर्पेक्षता के पक्षधर हैं। आज जब साम्राज्यवादियों द्वारा समर्थित फूटपरस्त ताकतें पहले ही बहुत सक्रिय हैं, बहुराष्ट्रीय निगमों का बढ़ता प्रभाव, बढ़ा भारी खतरा पैदा कर रहा है। सीटू को इस संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।

पीअरलेस का राष्ट्रीयकरण करो

सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने पीअरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि. के राष्ट्रीयकरण की मांग की है। याद रहे कि पुरस्कार चिट तथा भत्ता संचालन योजना (प्रतिबंध) कानून 1978, के तहत इस कंपनी को व्यापार करने से रोक दिया गया है। सीटू अध्यक्ष ने 21 मार्च को दिल्ली में जारी एक बयान में कंपनी के 4 लाख फील्ड आफिसरों 4000 आफिस कर्मचारियों तथा 2 करोड़ से ज्यादा सर्टिफिकेटधारियों की नियति पर चिंता प्रकट की है, जो कंपनी का व्यापार बन्द किये जाने से प्रभावित होंगे। सीटू की राय है कि भारत सरकार द्वारा इस कंपनी के अधिग्रहण तथा राष्ट्रीयकरण से ही सभी सम्बद्ध लोगों के हितों की रक्षा हो सकती है।

सीटू के बयान में इस बात को रेखांकित किया गया है कि इस सिलसिले में पीअरलेस एंजलाइज यूनियन (सीटू) ने वित्त मंत्री को अनेक जापन दिये हैं तथा संसद के दोनों सदनों के अनेक संघर्षों ने वित्त मंत्री को जापन बेकर इस कंपनी के राष्ट्रीयकरण की मांग की है। इसके बावजूद, इस सिलसिले में सरकार ने प्रथम तक कोई कदम नहीं उठाया है। इस स्थिति में, सीटू ने इस कंपनी के कर्मचारियों के संघर्ष के लिए अपना पूर्ण समर्थन दुहराया है और अपनी सभी राज्य कमेटियों तथा संबद्ध यूनियनों का आह्वान किया है कि इस कंपनी के राष्ट्रीयकरण के लिए आवाज उठावें।

सौदू जनरल काउंसिल द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव

शहीदों पर

कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल 1986 तक सम्पन्न सौदू जनरल काउंसिल की यह बैठक उन शहीदों की याद में अपने खालभंडे को भुकाती है जिन्होंने मजदूरस्वयं-य मेहनतकश जनता के हितों के प्रति अपने समर्पण के कारण मालिकान के गुंडे व पुलिस हमलों के तहत अपने जीवन का बलिदान दिया। यह बैठक उन शहीदों के अचूरे काम को पूरा करने की शपथ लेती है।

प्रोलोफ पाल्मे

कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक सम्पन्न सौदू की यह जनरल काउंसिल की बैठक, स्वीडन के प्रधान मंत्री ओलोफ पाल्मे, जिनकी 1 मार्च को नृसंहार एवं कायरतापूर्ण ढंग से हत्या की गई, के निधन पर गहरे शोक का इजहार करती है। ओलोफ पाल्मे विश्व शांति की स्थापना तथा अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध सजिष्यों के खिलाफ संघर्ष में लगातार और जोरदार ढंग से नेतृत्वकारी भूमिका अदा करने वाले चुने गिने नेताओं में थे। वे नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए छः देशों के अभियान के अग्रणी में हस्ताक्षर करनेवालों में थे। उनके निधन पर, विश्व ने शांति के पक्षधर एक महान् योद्धा को खो दिया है। यह बैठक दिवंगत ओलोफ पाल्मे को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

कामरेड रामदास

कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक सम्पन्न सौदू की यह जनरल काउंसिल का. रामदास के आकाशिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है उनकी मृत्यु 8 नवम्बर 1985 को दिल्ली में हुई। वे 60 वर्ष के थे। मृत्यु के समय वे सी पी आई (एम) के केन्द्रीय कमिटी के सदस्य तथा पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी के कार्यकारी सम्पादक थे। उनका राजनैतिक जीवन 1942 में पार्टी सदस्य के रूप में चालू हुआ और 17 वर्ष की छोटी सी आयु में का. रामदास ने स्वतंत्रता आन्दोलन को समर्थन देते हुए सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद की लाइन का जनता के बीच प्रचार आरम्भ कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी की इस राजनैतिक विचारधारा को आगे बढ़ाया कि सोवियत संघ की अगुवाई में चलाई जा रही फासीविरोधी संघर्ष में सक्रीय हिस्सेदारी ही देश को आजाद करने का एकमात्र रास्ता है। वे 1947 में पार्टी प्रेस बम्बई चले आये तथा काम रोड नामक साप्ताहिक में सक्रिय रूप से काम करने लगे। एक समर्पित कामरेड होने की हैसियत से और मार्क्सवाद लेनिनवाद पर पूरा विश्वास रखते हुए का. रामदास ने वामपंथी व दक्षिण पंथी भटकावों के खिलाफ लड़ाई में कभी कोई समझौता नहीं किया। न्यू एज में कार्यरत रहने के दौरान का. रामदास ने पार्टी में बढ़ते सुधारवादी रुझानों के खिलाफ निरंतर लड़ते रहे। अंत तक उनके सैद्धांतिक और सांगठनिक विचारधारा ही

1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में काफी हद तक मदद किया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के बाद करीब करीब सारे नेताओं को भारत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे समय में विचलित न होकर का. राम दास ने अपना काम उसी लगन से जारी रखा व नई पार्टी को सहारा देकर अकेले ही पीपुल्स डेमोक्रेसी का प्रकाशन शुरू कर दिया। 1968 में वे केन्द्रीय कमिटी के सदस्य चुने गये मार्क्सवाद — लेनिनवाद के सिद्धांतों की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ जोड़ने का क्रांतिकारी कार्य का. रामदास ने अपनी अन्य जिम्मेदारी निभाते हुए किये। यह बैठक का. रामदास की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनकी पत्नी का. किटी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपने गहरे समवेदना का इजहार करती है।

श्रद्धांजलि पर

कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल, 1986, तक सम्पन्न सौदू जनरल काउंसिल की यह बैठक सौदू जनरल काउंसिल के सदस्य कामरेड पी. लक्ष्मीदास एवं उन सारे सदस्यों के निधन पर गम्भीर शोक का इजहार करती है जिन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है। यह बैठक उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपने गहरे समवेदना का इजहार करती है।

ए यू सी सी टी यू के प्रस्ताव पर

कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल 1986 को सम्पन्न सौदू की यह जनरल काउंसिल बैठक सी पी एस यू के महासचिव का. एम एस गोर्बाचव द्वारा 15 जनवरी 1986 को दिए गए वयान पर आधारित ऑल यूनियन सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियनस, सोवियत संघ की अपील का गर्मजोशी से स्वागत करती है जिसमें सोवियत संघ ने मानवजाति के सम्पूर्ण विनाश का आज जो भयानक खतरा पैदा हो गया है उसे 2000 ई. तक तीन चरणों में समाप्त करने के उद्देश्य से नाभिकीय व रसायनिक हथियारों के सम्पूर्ण उन्मूलन के प्रस्ताव पेश किया है।

आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की मुख्य बात यह है कि अमरीकी साम्राज्यवादी, समाजवादी सोवियत संघ के खिलाफ और समाजवादी लेमे के खिलाफ नाभिकीय युद्ध की मुहिम चला रहे हैं। यह युद्ध दुनिया भर पर फिर से प्रचलित कायम करने की अमरीका की अगुवाई में चल रही साम्राज्यवादी मुहिम का ही हिस्सा है। लेकिन समाजवादी शिबिर की सैनिक और सैद्धांतिक शक्ति उनकी इस साजिश के आड़े आ रही है। इसलिए अमरीकी

साम्राज्यवादी, सोवियत संघ पर सैनिक बढ़त हासिल करना चाहती है ताकि उसके खिलाफ युद्ध छेड़ें सकें।

अमरीका की इन युद्ध योजनाओं के विपरीत सोवियत संघ ने अनेक शांति प्रस्ताव पेश किए हैं। नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण पर एकतरफा रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है तथा नाभिकीय अस्त्रों का प्रथम प्रहार न करने का ऐलान किया है। और इन तमाम पहलकदमियों को अमरीका ने ठुकरा दिया है। दरअसल, तथाकथित रणनीतिक सुरक्षा पहल यानि अंतरिक्ष युद्ध कार्यक्रम के पीछे मंशा ठीक प्रथम नाभिकीय प्रहार की ही है।

इस संकटपूर्ण स्थिति में, जब राष्ट्रसंघ ने 1986 को शांति के वर्ष के रूप में घोषित किया है जैसा कि ए यू सी सी टी यू अपील में कहा गया है, दुनिया की व्यापक नरसंहार के अस्त्रों से मुक्त कराकर तीसरे सहस्राब्दी में ले जाने का का. एम. एच. गोर्बाचव द्वारा की गई पेशकशों की यह बैठक बिस्व शांति स्थापना की दिशा में एक शानदार योगदान मानती है और इसे सम्पूर्ण रूप से समर्थन देती है।

यह बैठक, ए यू सी सी टी यू को, और उसके जरिए सोवियत संघ की जनता को यह आश्वासन देती है कि सौदू तथा भारत का मजदूर वर्ग अपनी क्षमता के अनुकूल यह सुनिश्चित करने की हर सम्भव प्रयास करेगी कि हमारे भाइयों और बहनों को फासीवादियों द्वारा छेड़े गए दूसरे बिस्व युद्ध के उन भयानक दिनों में फिर से श्वास जाना न पड़े जिसमें सोवियत संघ के दो करोड़ सहित पांच करोड़ प्राणों का बलिदान देना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति यही हमारा शपथ है कि सौ साल से ज्यादा अस्त्रों में सर्वहारा वर्ग ने संघर्ष के जरिए जो जीतें हासिल की है, जो कामयाबियाँ पाई है उसे हम सामराज्यवादियों को छीनने नहीं देंगे।

यह बैठक अपने राज्य कमेटीयों तथा सम्बद्ध सभी यूनियनों का साह्वान करती है कि वह मई दिवस शताब्दी के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इन प्रस्तावों को, हर तबके के मजदूरों, ट्रेड यूनियनों, अन्य जन संगठनों तथा जनवाद व शांति में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच, लोकप्रिय बनाने के लिए जोरदार अभियान चलाएँ, और शांति के लिए संघर्ष को निरन्तर आगे बढ़ाते रहे और साम्राज्यवादी युद्ध साजिशों को शिकस्त दें। यह बैठक अन्य सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि नाभिकीय विनाश से मानव जाति को बचाने के लिए व्यापक शांति आंदोलनों में शामिल हों।

अफगानिस्तान और एंगोला में अमरीकी प्रक्षेपनास्त्रों पर

कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल 1986 तक सम्पन्न सौदू जनरल काउंसिल की यह बैठक, अफगानिस्तान तथा एंगोला

की प्रतिक्रांतिकारियों की मदद के लिए और साथ-साथ निकारागुवा तथा कैम्बोडिया के खिलाफ अत्याधुनिक "स्ट्रीगर" एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजने की रीगन प्रशासन के फैसले की तीव्र भर्त्सना करती है। अमरीका की यह कार्रवाई, लीबिया पर सैनिक कार्रवाई चलाने की घमकी और लीबियायी समुद्रीतट पर युद्धपोत भेजे जाने की कार्रवाई के पीछे पर ही की जा रही है। रीगन प्रशासन की यह उजड़ड़ताभरी कार्रवाई, दुनिया को अपने काबिज में लेने तथा हर जगह कठपुतली तानाशाही सरकार कायम करने की तथा बिस्व भर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की मुहिम को ही बेनकाब करता है जबकि सोवियत संघ ने बिस्व शांति की स्थापना के लिए कई नए ठोस प्रस्ताव पेश किए हैं।

यह बैठक, रीगन प्रशासन से अपनी उजड़ड़ता भरी कार्रवाईयों को तत्काल बन्द करने की मांग करती है तथा सम्बद्ध सभी यूनियनों का आह्वान करती है व अन्य सभी ट्रेड यूनियनों व शांतकामी लोगों से अपील करती है कि इसके विरोध में अपने आवाज को बलुन्द करें।

पंजाब की घटनाओं पर प्रस्ताव

कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक सम्पन्न सौदू जनरल काउंसिल की यह बैठक पंजाब में बिगड़ती हुई स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है। पंजाब समझौते का उल्लंघन हो चुका है, जनता के सभी हिस्सों ने स्वागत किया। समझौते के बाद हुए चुनावों में अकाली पार्टी को जनता का भारी बहुमत प्राप्त हुआ। चुनावों के बाद जनता को यह उम्मीद थी कि अकाली सरकार उप्रपंथियों को अलग चलन करके पंजाब की स्थिति को सामान्य करने में समर्थ होगी। किन्तु विशाल जनमत के बावजूद अकाली सरकार उप्रपंथियों की चुनौती को स्वीकार करने में असमर्थ रही है। और उन्होंने उप्रपंथियों की तरफ एक समझौता पूर्ण नीति अपनाई है। इससे उप्रपंथियों के होसले और बलुन्द हुए व उन्होंने अपनी धुसापूर्णे गतिविधियों को तेज करने के लिए स्वर्ण मंदिर सहित कई और गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब निर्दोष लोगों की हत्याये नहीं होती। जालंधर और लुधियाना में जारी व्यापक हत्यायों और स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाली दल कार्यलयों में आगजनी की घटना इसी बात को दिखाता है कि किस हद तक उग्रवादी अपने हकतों को बेरोक-टोक चलाने में सफल हो रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अपना अधिपत्य जमाने में नाकामयाब रही है। यहाँ तक कि उसने, उग्रवादियों के डर से सर्वत खालसा का स्थान अनुत्तर से बदलकर आनन्द पुर साहिब कर दिया। सर्वत खालसा ने यह फैसला लिया था कि गुरुद्वारों को उप्रपंथियों से मुफ्त कराया जायेगा पर अकाली इस फैसले को भी पूरा नहीं कर पाये। जहाँ एक तरफ अकाली सरकार ने उप्रपंथियों के सामने घुटने टेक दिये हैं वहीं दूसरी ओर केन्द्र की कांग्रेस (आई) सरकार भी अपने दुलमुल व लापरवाह नीति से

मामलों को विगड़ने दे रही है। पंजाब समझौते का लागू न किया जाना कांग्रेस सरकार की निकम्मेपन का पर्दाफाश करता है। पंजाब समस्या के सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार की दुमुहुरी नीति हरिबाराण के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं से साफ उजागर होती है बल्कि अमरीका, ब्रिटेन जैसे सागराजी देशों तथा पाकिस्तान के फौजी निजाम को भी अपने षडयंत्रकारी मनसूबों में मदद मिली है व इससे खालिस्तानी उग्रपंथियों की स्थिति मजबूत हुई है।

यदि स्थिति को और विगड़ने दिया गया तो इससे देश में अस्थिरता पैदा होगी और देश की एकता को गम्भीर खतरा पैदा होगा। इसलिए, सीढ़ की यह जनरल काउंसिल बैठक केन्द्रिय सरकार तथा पंजाब की आकांक्षी सरकार से यह मांग करती है कि वे उग्रवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठावें व अपना हुलमुल रबैया छोड़कर पंजाब समझौते को पूरी तरह से लागू करें। यह बैठक राज्य में सांप्रदायिक सदभाव कायम करने तथा इन अलगाववादी ताकतों को अलग-थलग करने के लिए चलाए गए निरंतर संघर्ष के लिए पंजाब राज्य कमेटी को बधाई देती है। पंजाब के पांच बाम पाटियों द्वारा 5 अप्रैल को पंजाब वचाओ दिवस मनाने के फैसले का भी यह बैठक स्वागत करती है और राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आह्वान करती है।

असम पर प्रस्ताव

कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित जनरल काउंसिल की यह बैठक असम में विपक्षी दलों तथा ट्रेड यूनियनों, खासकर सी पी आई (एम) व सीढ़, पर जारी बढ़ते हमलों के विषय में गहरी चिन्ता व्यक्त करती है।

यह हमले उस गैर जनवादी असम समझौते के बाद भी जाते हैं, जिसके द्वारा भारत सरकार ने सामराज्यवाद समर्थित पृथक्तावादी शक्तियों के सामने घुटने टेक दिये, असम गण-परिषद सरकार द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन राज्य में शांति और सौहार्द का माहौल खड़ा करने में तथा राज्य के भाषायी अल्पसंख्यकों और जातीय समुदाय के मन में विश्वास और आस्था कायम करने में असफल रही है। अब भी लूट, आगजनी, हत्याएँ, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार आदि आतंकवादी हमलों का सामना विपक्षी पार्टों के सदस्यों तथा समर्थकों को करना पड़ रहा है।

इसके साथ-साथ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में असमिया भाषा अनिवार्य कर दी गयी है इन में ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ अरसे से जनजातियों की मातृभाषा में शिक्षा दी जाती रही है। असम सरकार की आरक्षण विरोधी नीतियों से हरिजन, जनजातियों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों में भारी आक्रोश है।

यह सम्मेलन इस बात को भी नोट करता है कि असम सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही है कि जिसके द्वारा वो हजारों अल्पसंख्यकों को विदेशी करार देकर राज्य से बाहर निकाल देगी।

उपरोक्त घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि असम के राष्ट्र विरोधी विध्वंसकारी अराजकता आज भी सक्रिय है और इस कारण असम तथा राष्ट्र की अखण्डता को खतरा आज भी बरकरार है। असम में शांति और भाइचारे का वातावरण कायम होने की प्रधानमंत्री के दावे बिलकुल बेबुनियाद है।

यह बैठक असम सीढ़ तथा सी पी आई (एम) को इस खतरनाक षडयंत्र के खिलाफ दृढ़ संघर्ष करने के लिए बधाई देती है जैसाकि 26 फरवरी को राज्य भर हुए एकजुट संघर्ष से स्पष्ट है व साथ ही साथ इन अलगाववादी गतिविधियों की निन्दा करते हुए भारत तथा असम राज्य सरकार से मांग करती है कि वो अपनी हुलमुल नीतियों को छोड़ दे व देश की एकता व अखण्डता के लिए इन तत्वों व रूम्हानों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। यह बैठक अपने राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे बाम एवं जनवादी तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को लामबंद करने और इन पृथक्तावादी तत्वों की हकतों को वेनकाव करने की अपने जिम्मेदारियों को जारी रखते हुए पूरा करें।

दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद पर

कलकत्ता में 31 मार्च से 2 अप्रैल 1986 तक सम्पन्न सीढ़ जनरल काउंसिल की यह बैठक बर्बर नस्लवाद की नीति को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादपरस्त सरकार की यथेष्ट निन्दा करती है। श्वेत अल्पसंख्यकों की इस जघन्य और भयानक रूप आज संघर्षरत दक्षिण अफ्रीकी जनता पर चलाई जा रही बर्बर दमनारमक कार्रवाइयों में देखा जा सकता है। उस नित्यक मुक्ति योद्धा नेलसन मंडेला को पिछले दो दशक कैद रख अल्पसंख्यक सरकार ने नस्लवाद विरोधी पुष्पा कवि बेंजामिन मोलदस सहित अन्य सैकड़ों की हत्या की है। हत्याएँ, व्यापक गिरफ्तारियाँ, पुलिसी अत्याचार और हमने एक नियम सा बन गया है। यह बैठक अमरीकी तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की भी तीव्र भर्त्सना करती है जिन्होंने विश्व-जनमत की उपेक्षा करते हुए तथा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक पारंबंधों लगाने की राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को वीटो अधिकार के बल पर रद्द करते हुए बड़ी श्रेष्ठता से नस्लवाद परस्त हुजूमत को समर्थन दे रहे हैं। अमरीका और ब्रिटेन की यह विघनोना साजिश, बहुराष्ट्रीय निगमों के निर्देश पर दक्षिण अफ्रीका की सम्पदा लूटकर बेतहाशा मुनाफा कमाने की उनकी उपनिवेशवादी नीतियों का ही हिस्सा है। दरअसल, रीघन की कथित रचनात्मक विनियोग घोषणा (constructive engagement pronouncement) की नीति यही है—2 करोड़ 20 लाख (शेष पृष्ठ 21 पर)